

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
त्वरित न्यायालय परिसर, देहरादून ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 24 मार्च, 2008

विषय- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मा० न्यायमूर्ति श्री पी०सी०वर्मा द्वारा देहरादून में किराये पर लिये गये आवास के किराये के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5-दो(5)/XXXVI(1)(2)/2007-1-दो(5)/07, दिनांक 1.8.07 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मा० न्यायमूर्ति श्री पी०सी०वर्मा द्वारा देहरादून में किराये पर लिये गये आवास के किराये के भुगतान हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपशीर्षक के अधीन 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व का मानक मद न होने के कारण मा० अध्यक्ष को अनुमन्य किराये का भुगतान मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय से किये जाने हेतु मद संख्या-42-अन्य व्यय से रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) एवं विशेष परिस्थिति में संलग्न बी०एम० 15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम० 15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-42-अन्य व्यय में रु० 80,000/- (अस्सी हजार रुपये मात्र) की धनराशि के व्यावर्तन के पश्चात् मद संख्या-42-अन्य व्यय में कुल रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (I) उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल मा० कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुमन्य किराये का ही भुगतान किया जाय तथा शेष धनराशि शासन में समर्पित कर दिया जाय ।
- (II) प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 में अंकित कर उपलब्ध कराया जाय ।
- (III) उक्त धनराशि बजट मैनुअल के सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी ।
- (IV) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।
- (V) इस प्रकार के पुनर्विनियोग को भविष्य में दृष्टान्त न माना जाय ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या यू०ओ०1571/XXVII(5)/2008, दिनांक 24.3.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : बी०एम०-15

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 18-दो(5)/XXXVI(1)/2007-1-दो(5)/07-तददिनांक ।

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।

बी. एम.-15

पुनर्विनियोग 2007-2008 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ।
प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

1	2	3	4	5	6	7	8
बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जाती है ।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00-42-अन्य व्यय	300	50	100- क	2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00-42-अन्य व्यय	140	220	क-बचत होने के कारण । ख- प्राविधान कम एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
	300	50	100	80	140	220	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

संख्या-1571-क/वित्त अनुभाग-5/2008

देहरादून : दिनांक : 24 मार्च, 2008

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(दीपक सिंह)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या-18-दो(5)/XXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषधिकारी, देहरादून ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव